(ग) यदि हां, तो उक्त एकक को दाहोद से स्थानांतरित न होने देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) देश में ऐसे कितने अन्य डीजल इंजन और लोको शेड मरम्मत एकक कार्यरत हैं और क्या उनमें से कुछ एककों के बन्द होने की संभावना है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं। दाहोद में कोई डीज़ल रेल इंजन शेड नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय रेलों पर 62 डीजल रेल इंजन शेड हैं। उनमें से किसी भी डीज़ल रेल इंजन शेड को बंद करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

MEA Officials views on Pakistan

2212. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news item captioned "MEA Officials for tougher line on Pakistan", which appeared in the Times of India, dated 2nd August, 1995; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and steps proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Government have seen the news item captioned "MEA officials for tougher line of Pakistan" which appeared in the Times of India of 2nd August, 1995.

(b) Government's foreign policy, including, its policy towards Pakistan, is formulated in the overall national interest.

Role of ITI under National Telecom Policy

2213. SHRI S. JAIPAL REDDY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Public Sector ITI Ltd. is now required to produce and supply telecom equipments wanted by the Deptt. of Telecom (DOT) based on lowest quotations by competing with Private Sector on a level playing field;

(b) whether the Private Sectors alongwith foreign companies is now also allowed to enter the basic telecom services while the ITI Ltd. is not being permitted to do so under the National Telecom Policy;

(c) if so, whether Government would revise this decision and agree to allow the ITI Ltd. to enter the basic telecom services; and

(d) what are the plans of Government to provide an effective role to the ITI Ltd. in the light of the National Telecom Policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir. However, with a view to utilise optimally infrastructure of the two PSUs viz. ITI & HTL under Ministry of Communications, the Ministry is following a policy under which 30 to 35% of total DOT orders are kept reserved for ITI & HTL, taken together, for those items which they manufacture. However, this policy is without any compromise in respect of quality, delivery schedule and pricing. The pricing is governed by the process of tendering.

(b) Indian companies registered under the Indian Companies Act, 1956 except the Government Companies have been permitted to bid against the tender floated for the provision of Basic Telecom Services.

(c) It has been decided to preclude the Government Companies including ITI from the basic services as these undertakings have been established by the Government for specific purposes and have sufficient potential for growth in their respective areas. Moreover, Government is keen to ensure a

purposeful competition between a Government operator (DOT) and a private operator and not between two Government operators.

(d) ITI will be expected to meet the demand of the DOT and Private Service operators for equipment in competition with other manufacturers. It will also be expected diversify its products as well as customers.

अरावली पहाड़ियों में भूमि सुधार

2214. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा राज्य में अरावली की पहाड़ियों में कृषि उत्पादन के साथ-साथ इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी का विकास करने एवं चारा उगाने की दृष्टि से वहां भूमि सुधार से संबंधित एक परियोजना शुरू करने के लिए यूरोपीय समुदाय के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) इस करार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार मध्यप्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा के पठार क्षेत्रों और पहाड़ियों में इस प्रकार की परियोजना को कार्यान्वित करने का विचार रखती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) मार्च, 1990 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने "अरावली की पहाड़ियां, हरियाणा में सामुदायिक भूमि का पुनरुद्धार" नामक परियोजना को अनुदान के रूप में 23.20 मिलियन इसीयू देकर वित्तपोषित करने का आश्वासन दिया है। यह परियोजना 1990 से कार्यान्वित की जा रही है। समझौते के अनुसार, परियोजना की कुल लागत, 48.15 करोड़ रुपए हैं इसको भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में सात वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। इस परियोजना में अर्ध-शुष्क अरावली पहाड़ियों में पर्यावरणीय सुरक्षा और हरे आवरण की बहाली की संकल्पना की गई है ताकि स्थानीय लोगों की जीविकोपार्जन जैवमास जरूरतों को पूरा करके उनके जीवनस्तर में सुधार लाया जा सके। स्थाई आधार पर ईंधन की लकड़ी-इमारती लकड़ी, घास और चारा प्रदान करने के लिए इस परियोजना के तहत 33,000 हैक्टेयर सामुदायिक भूमि को कवर किया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मिट्टी की उर्वरता बेहतर होगी। भूमि का कटाव रुकेगा और जल विज्ञान संबंधी संतुलन में सुधार होगा जिससे उस क्षेत्र में कृषि उत्पादन को लाभ पहुंचेगा।

(ग) विश्व बैंक की सहायता से 245.94 करोड़ रुपए की लागत से 1995-96 के दौरान विंध्याचल एवं सतपुड़ा के पठार और पहाड़ियों सहित समूचे मध्यप्रदेश राज्य को शामिल करने वाली एक वानिकी योजना शुरू की गई है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, वनों की उत्पादकता बढ़ाना और वनों व कृषि भूमि पर वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि करना है। यह परियोजना 4 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी।

Industrial thefts and pilferages in Jamshedpur

2215. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Industrial thefts and pilferage have been reported from Jamshedpur, the steel city as reported in the Telegraph dated 18th June, 1995; and

(b) if so, the steps taken to eradicate such inter-state organised rackets?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Running of DMU trains in Orissa

2216. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of DMU trains running in different routes of Orissa as on 30th October, 1994;

(b) whether some of those DMU trains have been withdrawn from those routes;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether Government propose to consider the re-introduction of DMU trains in some of those routes; and

(e) if so, the details thereof?